in that journey on the AC two-tier pass provided for the companion vide 6B(ii) above, then the amount of oneAC two-tier fare for such journey is adjusted against the amount payable by the member under clause 6B(i) above.

There is no discrimination in regard to the entitled class of travel in-as-much-as both the member and spouse have been provided free rail pass for AC iwo-tier.

The Joint Committee on Salaries and Allowances of Members of Parliament have in the past made recommendations for providing free AC 1st Class rail passes for the MP, Spouse and companion and the matter had been under consideration of the Government. It has not been found feasible to make provision for AC 1st Class pass even for the MPs on account of administrative difficulties.

Steps taken to increase female literacy in the Country

94. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what steps are being taken by Government to increase female literacy in the country, particularly in the backward rural districts;

(b) whether Government have formulated any special schemes for promoting female literacy in the country through voluntary organisations', and

(c) if so, the details thereof; and if not, the reasons therefore?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) Trie Scheme of Universalisation of Elementary Education, Non-Formal Education for School Drop outs, Total Literacy Campaigns of the National Literacy Mission form the three pronged strategy for increasing female literacy in the country. There are no separate schemes for backward rural districts.

(b) and (c) No special scheme has been formulated by the Government for promoting female literacy exclusively through voluntary organisations. However, under all the schemes mentioned in reply to part (a) above, the stress is laid on securing participation of voluntary organisations for promotion of female literacy.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सरकारी आवास का 'बिना बारी' आवंटन

95. श्री गोविन्द राम मिरी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1992 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को 'बिना बारी' आवंटन आधार पर सरकारी आवास आवंटित किए गए थे;

(ख) क्या इन अधिकारियों पर कुछ लाख रुपयों का किराया बकाया था; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोल इंडिया लिमिटेड की "अपने स्वामित्व वाली कोयला खान बनाओ और चलाओ" योजना

96. श्री अजीत जोगी: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड का "अपने स्वामित्व वाली कोयला खान बनाओ और चलाओ" योजना को कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के प्रति गैर-सरकारी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया रही;

(ग) इससे कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में कोयले के मूल्यों में वृद्धि की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) जी, हां। ग्रहीत विद्युत संयंत्र कोयला वाशरियों तथा "स्व-निर्मित स्व-चालित" योजना के अंतर्गत फाइन प्राप्त संयंत्रों को स्थापित किये जाने संबंधी प्रस्ताव विद्यमान हैं।

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना